

[2026:RJ-JP:31039]



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 8984/2026

CNR: RJHC010392862026

URN: CW / 16527U / 2026

Vivek Joshi S/o Shri Ramesh Chandra Joshi, Aged About 32 Years, Presently Working As Head Constable No.11/413 In Rajasthan Police Department, (Police Station Salumbar) Resident Of Village Gamothwara, Sagwara, District Dungarpur (Raj.)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Home Department, Government Of Rajasthan, Jaipur.
2. Director General Of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. Superintendent Of Police, Salumbar, District Salumbar (Raj.)

-----Respondents

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 12405/2026

CNR: RJHC010552842026

URN: CW / 22520U / 2026

Vivek Joshi S/o Shri Ramesh Chandra Joshi, Aged About 32 Years, Presently Working As Head Constable No. 11/413 In Rajasthan Police Department, (Police Station Salumbar) Resident Of Village Gamothwara, Sagwara, District Dungarpur (Raj.)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Home Department, Government Of Rajasthan, Jaipur.
2. Director General Of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. Inspector General Of Police, Udaipur Range, District Udaipur (Raj.)
4. Superintendent Of Police, Salumbar, District Salumbar (Raj.)

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Mohit Sharma
Mr. Ojas Shakdwipeeya
For Respondent(s) : Mr. Raj Singh Bhati,
Mr. Shailendra Kumar &
Mr. Paramvir Singh, for
Mr. Rituraj Singh Bhati, GC

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

13/07/2026

याची पुलिस विभाग में कांस्टेबिल के रूप में नियुक्त कर्मचारी है तथा उसके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित, 2018) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2025 पंजीबद्ध होने के उपरांत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी और उसके उपरांत दिनांक 14.04.2026 के आदेश के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी द्वारा उसे निलंबित किया गया। उसके उपरांत दिनांक 26.05.2026 के आदेश के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा याची का मुख्यालय जिला सलूमबर से बदलते हुए प्रतापगढ़ किया गया।

एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 8984/2026 के माध्यम से निलंबन आदेश दिनांक 14.04.2026 को तथा एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 12405/2026 के माध्यम से मुख्यालय परिवर्तन के आदेश दिनांक 26.05.2026 को चुनौती दी गयी है।

विद्वान अधिवक्ता अयाची की प्रारंभिक आपत्ति यह है कि उपरोक्त दोनों ही विवाद/विषय राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामले अपील अधिकरण) 1976 की धारा 2 (एफ) के तहत "सेवा मामलों" में समाहित है और इन विवादों के निस्तारण हेतु राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष प्रभावी व वैकल्पिक उपचार याची को उपलब्ध है और ऐसे मामलों में इस न्यायालय द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं

है और इसी आधार पर यह दोनों याचिकाएं खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 14863/2016 नारूलाल मेघवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025, एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 3673/2022 करन कुमार मेघवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 तथा एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 221/2021 राम निवास बिश्नोई बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.01.2023 की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि निलंबन आदेश तथा मुख्यालय परिवर्तन के मामलों में इस न्यायालय द्वारा अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया गया है और वर्तमान मामले भी उसी श्रेणी के हैं।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 19780/2023 निधि सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 23.01.2024 में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा डी.बी.स्पेशल अपील रिट नंबर 662/2022 जहांगीर अली खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2022 का अनुसरण करते हुए यह व्यवस्था प्रतिपादित की है कि निलंबन संबंधी विवाद अधिनियम, 1976 की धारा 2(एफ) के क्लॉज-5 में आता है और जहां प्रभावी व वैकल्पिक उपचार याची को उपलब्ध है तो उस स्थिति में अपवादिक मामलों को छोड़ कर संवैधानिक न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का उपयोग किया जाना उचित नहीं है।

निधि सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (पूर्वोक्त) के निर्णय के पैरा संख्या 6, 7 व 8 निम्नानुसार है :—

6. Having heard the learned counsel for the parties and upon perusal of the record, it is noted that the petitioner would fall under the definition of 'government servant', as prescribed under Section 2(c) of Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunals) Act, 1976

(for short "Act of 1976"). Further, the *lis* in question is also covered under the definition of 'service matters', as prescribed under Section 2(f) of the Act of 1976. The scope of 'service matters' has been considered by Division Bench of this Court in the case of Jahangir Ali Khan (supra), the relevant portion of which is reproduced as under:

"The first contention of the learned Additional Advocate General that the Tribunal had no jurisdiction to entertain the dispute regarding the validity of an order of suspension, cannot be accepted in view of wide definition of expression "Service matter" given under Section 2 (f) of the Act of 1976.

Section 2, sub-section (f), being relevant, is extracted hereinbelow:-

"(f) "Service matter" means any one or more than one of the following matters relating to a Government Servant:-

- (i) Seniority;
- (ii) Promotion;
- (iii) Confirmation;
- (iv) Fixation of pay;
- (v) An order denying or varying pay, allowances, pension and other service conditions to the disadvantage of a Government Servant, other-wise than as a penalty;
- (vi) Cases of reversion while officiating in a higher service, grade or post to lower service, grade or post other-wise than as a penalty;
- (vii) Withholding the pension or denying the maximum pension other-wise than as the penalty;
- (viii) Any other matter notified by the Government."

Clause (v) of sub-section (f) of Section 2 of the Act of 1976 is very wide. It reads that an order denying or varying pay, allowances, pension and other service conditions to the disadvantage of a Government Servant, other-wise than as a penalty would be covered under the expression "Service matter". The expression "any other service conditions to the disadvantage of a Government Servant" would obviously include the dispute arising on account of an action of suspending an employee under the service Rules. Given the wide definition under sub-section (f) as aforesaid, we have no reason to hold that it excludes suspension issue. Therefore,

the contention of Ld. Additional Advocate General with regard to jurisdiction on this aspect cannot be accepted and therefore rejected.”

7.The exercise of writ jurisdiction is fundamentally discretionary in nature. The limitations placed on Court's decision to exercise or refuse to exercise its writ jurisdiction are self-imposed. Although learned Senior Counsel for the petitioner rightly contends that the existence of an alternate remedy, whether adequate or not, does not alter the fundamentally discretionary nature of the writ jurisdiction, it remains a discretion nonetheless. Though the pleadings are complete, the present petition is still listed for admission. Therefore, this Court is of the considered view that since an alternate and efficacious remedy is available to the petitioner, this Court is not inclined to exercise the extra-ordinary jurisdiction.

8.The petitioner is granted liberty to approach RAT for redressal of her grievance. If the petitioner files appropriate petition before the RAT within a period of 30 days, the RAT shall adjudicate the same on merits as expeditiously as possible, preferably within a period of three months.

उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि राजकीय कर्मचारियों के निलंबन से संबंधित विवाद अधिनियम, 1976 की धारा 2 (एफ) के क्लॉज 5 के तहत आता है और ऐसे मामलों में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष उपचार प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मुख्यालय परिवर्तन का विवाद भी अधिनियम, 1976 की धारा 2 (एफ) क्लॉज-5 के तहत आता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State Bank of Travancore Vs. Mathew K.C. 2018 (3) एस सी सी 85 व Leelavathi N vs State of Karnataka 2025 SCC Online 2253 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि वैकल्पिक व प्रभावी उपचार उपलब्ध होने के बावजूद न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का प्रयोग किया जाना पूर्णतः वर्जित नहीं

है, परंतु सामान्य रूप से जहां वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय राम निवास बिश्नोई बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (पूर्वोक्त), करन कुमार मेघवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (पूर्वोक्त) तथा नारूलाल मेघवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में वैकल्पिक व प्रभावी उपचार व क्षेत्राधिकार का बिन्दु ना तो उठाया गया और ना ही निर्णीत हुआ है। इसके अतिरिक्त जहां एक ही बिन्दु पर एकल पीठ व खण्ड पीठ के अलग अलग अभिमत हो तो न्यायिक निर्णय (Law of Precedent) के सिद्धांत के अनुसार खण्ड पीठ का निर्णय ही आबद्धकर है।

इस न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय जहांगीर अली खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (पूर्वोक्त) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State Bank of Travancore Vs. Mathew K.C. (पूर्वोक्त) में पारित विधिक व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि जहां प्रभावी व वैकल्पिक उपचार याची को उपलब्ध है तो जब तक विशिष्ट व अपवादिक परिस्थितियां नहीं हो, इस न्यायालय द्वारा सीधे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 की शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय Leelavathi N vs State of Karnataka (पूर्वोक्त) का सुसंगत पैरा संख्या 36, 37 व 38 निम्नानुसार है :-

36. A careful perusal of the aforesaid judgments leads us to the conclusion that where an efficacious alternate remedy is available, the High Court should not entertain a writ petition under Article 226 of the Constitution of India in matters falling squarely within the domain of the Tribunals.

37. Nevertheless, a writ petition under Article 226 may still be maintainable notwithstanding the existence of such an alternative remedy in exceptional circumstances, including the enforcement of fundamental rights guaranteed under Part III of the Constitution; instances of ultra vires or illegal exercise of power by a statutory authority; violation of the principles of natural justice; or where the vires of the parent legislation itself is under

challenge. While these exceptions have been carved out and reiterated by this Court in a catena of decisions, the facts of the present case do not fall within any of these exceptions so as to warrant the maintainability of the writ petitions before the High Court.

38. The Act of 1985 empowers the Tribunals to deal exclusively with service matters with the intention to reduce the burden on Courts, who were otherwise dealing with service matters along with the other cases. The idea behind establishing the Tribunals was to provide speedy reliefs to the aggrieved persons in respect of their grievances in relation to service matters.

एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 6510/2017 गोविंद देथा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 17.09.2019 को निर्णय पारित करते हुए यह व्यवस्था प्रतिपादित की है कि पदोन्नति का मामला राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा सुनवाई योग्य है और ऐसे मामलों में वहीं उपचार प्राप्त किये जाने की व्यवस्था देते हुए रिट पिटीशन पोषणीय नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया, इस निर्णय का सुसंगत भाग निम्नानुसार है :—

"Admittedly, promotion matter comes within the purview of jurisdiction of Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal where an appeal could be preferred by the Government Employee claiming promotion from an earlier order. Appellate jurisdiction of the Tribunal is much wider as it would call for the record relating to DPC and examine the case of the petitioner.

Taking into consideration the efficacious alternate remedy available to the petitioner, the writ petition is not maintainable in the view of the judgment passed by the Apex Court in the case of State Bank of Travencore Vs. Mathew K.C.12 reported in 2018(3) SCC 85.

In the view of above the writ petition is dismissed with liberty to approach the tribunal to redress his grievances."

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निलंबन आदेश तथा मुख्यालय परिवर्तन का आदेश अधिनियम, 1976 की धारा 2 (एफ) के क्लॉज 5 में समाहित है और ऐसे मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण को है। वर्तमान मामलों में ऐसी कोई अपवादिक या

विशिष्ट परिस्थितियां नहीं है जिसमें इस न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जावे।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है, अतः याची को विवाद विषय के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए यह दोनों याचिकाएं खारिज की जाती है तथा दोनों स्थगन प्रार्थना पत्र भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J